benefit of the House. I quote the terms of reference: 'To elucidate the factors responsible for the current outbreak of plague and its sperad'. Perhaps it includes what you said.

SHRI CHATURANAN MISHRA: The financial aspect is not included.

SHRI B. SHANKARANAND: The question is whether it would go into the financial aspect also. That also the Committee can look into.

SHRI CHATURANAN MISHRA: Then you make it clear. You write to the Committee that they can go into this also. I would be very happy.

SHRI B. SHANKARANAND: Yes.

SHRI INDER KUMAR GUJARAL: Sir, the hon. Minister has tried to underplay the situation. It is not a question of propaganda. It is not a question of the number of cases, whether it is more or less The issue, basically, is this. I think my hon. friend knows it. Not once, not twice, not thrice, but in the last forty or fifty years, there are any number of reports available and you do not need one more expert committee to tell you that excepting the N.D.M.C. no other municipality in the country is financially viable.

Now, the point is, if a plan has to be made obviously—I assume—the Government, like a corporate body, works together—may I ask the hon. Minister whether he had approached the Planning Commission on this issue that the financial structure of the municipalities had to be improved? This is one thing.

Secondly, has the hon. Minister thought in terms of improving the sanitation methodology and technology? It does not need a World Health Organisation report to tell us that our cities are dirty. It does not need any health organisation to tell us that there is filth all around, that we first collect the garbage on the roadside and then remove it and diseases spread all around. Sir, this incident of plague—I am not discussing its dimension—has brought us disrepute abroad and despair at home. May I ask him whether he is willing to undertake the task of evolving a scheme? This is apart from the work of the Committee; the Committee is to suggest ways to avoid this kind of a situation. I wrote to the Prime Minister. The Prime Minister wrote back to me saying that he had referred the issue to you and to the Ministry of Urban Development. May I know from the hon. Minister whether the Ministry of Health and the Ministry of Urban Development would sit together and evolve a comprehensive scheme to see that our health and sanitation improve?

SHRI B. SHANKARANAND: Sir, the hon. Member is right in his point about the maintenance of sanitary conditions by the municipalities. It does need to deep thought and a co-ordinated approach to solve this problem. It is not only the question of the Health Ministry. This also involves the Ministry of Urban Development, the State Ministries and the local authorities themselves.

As far as the question of funds is concerned, necessarily we have to find a way. We have to consult the Planning Commission. In that regard, the suggestion made by the hon. Member is well received.

Construction of overbridge near Sakhoti Tanda Railway Station

*203. SHRIMATI MALTI SHARMA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the road users are facing difficulties due to frequent closing of level crossing near Sakhoti Tanda Railway Station (N.R.);

(b) if so, whether there is any proposal under Government's consideration for construction of overbridge on the above level crossing; and

(c) if so, by when the work on the job is likely to be started?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. K. JAFFAR SHARIEF): (a) **Yes, Sir.**

(b) and (c) Yes, Sir. A Road overbridge for this location, was sanctioned and included in Railway's budget for the year 1987-88 but had to be dropped in 1991-92 as State Government failed to acquire land for construction of approaches. Railways are ready to build this Road overbridges, as soon as State Government is prepared to do so.

श्रीमती मालती शर्मा : सभापति महोदय, मैं यह जानकारी चाहती हूं, जैसा माननीय मंत्री जी ने यह तो स्वीकार किया कि है 1987-88 के बजट में इस पुल को स्वीकार कर लिया गया था, तो क्या केन्द्रीय मंत्री जी अपने को इतना निस्सहाय मान रहे हैं कि वह वहां की प्रदेश सरकार को यह आदेश नहीं दे सकते कि इतना महत्वपूर्ण लेवल क्रॉसिंग होते हुए यहां की भूमि का तुरन्त अधिग्रहण किया जाए ? क्या इसके लिए माननीय मंत्री जी आदेश देने का कष्ट करेंगे ?

SHRI C. K. JAFFER SHARIEF: Sir, there is no question of directing any State Government. Whenever such demands come, we do write to the State Government whether they are willing to take

part on a cost sharing basis. If the State Government responds, then we go ahead. If the State Government does not respond, we will not be able to do it. Here is very clear that the State Government did not acquire the land.

श्रीमती मालती शर्मा : माननीय सभापति जी, यह क्रॉसिंग इतना महत्वपूर्ण है कि यह तीन प्रान्तों को जोड़ता है । यह पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अंतिम छोर उत्तरकाशी तक जाता है । उस प्रदेश में अनेक तीर्थ स्थान होने के कारण सारे देश के यात्री यहां से गुजरते हैं । मान्यवर, मैं यह कहना चाहती हूं कि इस क्रासिंग पर दो वर्ष के अंदर कितनी दुर्घटनाएं और कितनी लूट-पाट की घटनाएं हो चुकी हैं, क्या माननीय मंत्री जी को इसकी जानकारी है ? इसके साथ ही साथ मै यह भी जानना चाहती हूं कि इतना महत्वपूर्ण क्रॉसिंग होते हुए क्या माननीय मंत्री जी ने कोई पत्र व्यवहार राज्य सरकार के साथ किया है कि वे तुरंत इसको डिसाइड करे ? मेरी जानकारी में यह भी है कि इस क्रॉसिंग के दोनो तरफ पी०डब्ल्यू०डी० की भी और रेलवे की भी जमीन इतनी पड़ी हुई है कि बिना अधिगृहित किए हुए भी यहा पर ओवरब्रिज बनाया जा सकता है । क्या माननीय मंत्री जी इसकी जानकारी करके तुरन्त इस पुल के लिए आदेश देने का कष्ट करेंगे ?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : सर, जहां तक रेलवे की जमीन का सवाल है तो उसमे तो कोई आपत्ति ही नहीं है, उससे तो किसी को पूछने का सवाल पैदा नहीं होता । जहां तक पी०डब्ल्यू०डी० की जमीन का सवाल है, वह स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, उनसे पूछना ही पड़ेगा । यहां जो शब्द इस्तेमाल किया गया है एक्वायर, एक्वायर करना पड़ता है प्राइवेट लेंड को। इसलिए मुझे नही लगता कि सिर्फ दोनों सरकारों की ही लैंड होगी, कोई प्राइवेट लैंड भी होगी, जिसके लिए कि एक्विजीशन करने की जरूरत पड़ेगी । जब तक स्टेट गवर्नमेंट एक्वायर करके सुविधा नही पहुंचाएगी, तब तक इस काम में आगे बढ़ना मुश्किल होगा । सर, माननीय सदस्या ने जिन बातो को उठाया है, मुझे उनसे सहानुभूति है, हम दोबारा स्टेट गवर्नमेंट को इसके बारे में लिखेंगे ।

श्री ईश दत्त यादव : मान्यवर सभापति जी, इटावा उत्तर प्रदेश में है और यह एक बड़ा रेलवे स्टेशन है, जहां से पूरब को जाने वाली तमाम गाड़िया गुजरती हैं । यहां एक अंडर ब्रिज बनाने के लिए जनता की मांग की और श्री जनेश्वर मिश्र जब रेल मंत्री थे तो इन्होंने जाकर अंडर ब्रिज का शिलान्यास भी कर दिया था इटावा में क्योंकि लोगों को बेहद इंतजार करना पड़ता है ...(व्यवधान)

SHRI S. JAIPAL REDDY: The Ministers are very good at doing *shilanyas!*

श्री ईश दत्त यादव : मान्यवर, श्री राम गोपाल जी, जो इस सदन के सदस्य हैं, इन्होंने भी स्पेशल मेंशन में इस सवाल को उठाया था ।

श्री संघप्रिय गौतम : मैंने भी उठाया था ।

श्री ईश दत्त यादव : मैंने भी अन-स्टार्ड क्वेश्चन मे इसको पूछा था । बीच में व्यवधान यह आ गया और रेल मंत्री जी का यह कहना था कि उत्तर प्रदेश में एक सरकार थी जो चली गई, उसने व्यवधान पैदा कर दिया था अंडर ब्रिज को बनाने में । अब उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह जी ने अनुरोध किया है रेल मंत्री से कि हम पूरा सहयोग करेंगे, उत्तर प्रदेश की सरकार पूरा सहयोग करेगी इस अंडर ब्रिज को बनाने के लिए । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि आप कब तक इस अंडर ब्रिज को पूरा करा देंगे ?

SHRI C. K. JAFFER SHARIEF: Sir, this question does not relate to this underbridge. This question is related to an altogether different bridge. However, Sir, if any State Government takes interest and comes with a positive approach, we will consider that request, based on merit and availability of funds.

श्रीमती सुषमा स्वराज : सभापति जी, चूंकि मंत्री महोदय ने प्रश्न के उत्तर में यह कहा है कि हालांकि 1987-88 में उन्होंने निर्णय ले लिया था इस पुल को बनाने का, मगर चूंकि राज्य सरकार भूमि अधिगृहित करने में असफल रही, इसलिए उन्होंने यह निर्णय छोड़ दिया । तो मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि रेल मंत्रालय इस तरह के पुल बनाने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाता है ? वे अपने स्तर पर यह जानकारी हासिल करते है कि यहां पुल बनाने की जरूरत है या राज्य सरकार उनको मांग भेजती है ? यदि वे अपने स्तर पर जानकारी हासिल करते हैं तो राज्य सरकार को वह आदेश क्यों नहीं देते कि वह भूमि अधिगृहित करे और ये पुल बनाने का काम करें ? क्या और राज्यों में भी महज इस वजह से आपने पुल बनाने का काम छोड़ा है कि राज्य सरकार भूमि अधिगृहित करने में असफल रही है ? यदि छोड़ा है तो उनके आंकड़े भी मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी ?

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.